

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 54

विधि एवं न्याय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़	75.00	359.67	434.67	84.95	508.84	593.79	91.20	338.94	430.14
	4.80	...	4.80
	75.00	359.67	434.67	84.95	508.84	593.79	96.00	338.94	434.94
(करोड़ रुपए)									
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं									
1.01 विधि कार्य विभाग	2052	...	12.15	12.15	...	13.26	13.26	...	12.49
1.02 विधायी विभाग	2052	...	4.15	4.15	...	4.45	4.45	...	4.27
1.03 न्याय विभाग	2052	...	0.64	0.64	...	0.67	0.67	0.10	0.72
1.04 संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग	2052	2.84	2.84	...	1.00
1.05 अन्य	2052	...	5.15	5.15	...	5.17	5.17	...	5.36
	जोड़	...	22.09	22.09	...	26.39	26.39	0.10	23.84
2. राज्य चुनाव के अंग									
2.01 चुनाव	2015	...	223.98	223.98	...	223.98	223.98
2.02 सामान्य चुनावी स्वर्च	2015	...	71.02	71.02	...	221.02	221.02	...	275.00
2.03 मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना	2015	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	जोड़	...	300.00	300.00	...	450.00	450.00	...	280.00
3. राजकोषीय सेवाएं									
3.01 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	2020	...	18.35	18.35	...	17.16	17.16	...	17.50
4. न्याय प्रशासन									
4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	2014	0.05	...	0.05	10.00	...	10.00	21.00	...
4.02 विशेष न्यायालय	3601	...	0.01	0.01
4.03 अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आई.सी.ए.डी.आर.)	2014	...	2.50	2.50	2.50
4.04 न्यायपालिका के लिए आधारदांचा संबंधी सुविधा हेतु बिना विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	2014	2.15	...	2.15	2.15	...	2.15	2.15	...
4.05 अन्य व्यय	2014	...	12.84	12.84	...	11.56	11.56	...	11.61
	जोड़	2.20	15.35	17.55	12.15	11.56	23.71	23.15	14.11
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं									
5.01 न्यायपालिका के लिए आधार-दांचा संबंधी सुविधाएं	3601	60.45	...	60.45	60.45	...	60.45	58.30	...
5.02 संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602	4.85	...	4.85	4.85	...	4.85	4.85	...
5.03 अन्य कार्यक्रम	2070	...	3.88	3.88	...	3.73	3.73	...	3.49
	जोड़	65.30	3.88	69.18	65.30	3.73	69.03	63.15	3.49
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	4.80	...
	4552	4.80	...
	जोड़	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	9.60	...
कुल जोड़		75.00	359.67	434.67	84.95	508.84	593.79	96.00	338.94
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.
1. न्याय प्रशासन	32014	67.50	...	67.50	77.45	...	77.45	86.40	...
2. एनईआर के लिए व्यय	22552	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	9.60	...
	जोड़	75.00	...	75.00	84.95	...	84.95	96.00	...

1.01 - 1.03 इसमें विभागों के सचिवालय व्यय तथा सर्वोच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायालयों सहित न्याय विभाग की नेटवर्किंग के लिए प्रावधान किया गया है।
1.04 यह प्रावधान संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग हेतु किया गया है।

1.05 यह प्रावधान राजभाषा स्कन्ध, जो केन्द्रीय अधिनियमों का हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उनकी छपाई के लिए जिम्मेदार है, के साथ-साथ एकीकृत मुकदमा अभिकरण के सचिवालय व्यय के लिए किया

गया है जो केन्द्रीय अभिकरण की योजना में सम्मिलित केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायलय में मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

2.01 आम चुनाव: यह प्रावधान आम चुनाव आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में उन्हें केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है।

2.02 यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को चुनावी व्यय से संबंधित केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है। इसमें मतदाता सूचियों आदि की तैयारी और छपाई को लागत भी शामिल है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की खरीद के लिए पृथक प्रावधान किया गया है।

2.03 यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने पर हुए व्यय के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है।

3.01 आयकर अपील न्यायाधिकरण की स्थापना मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर महानिदेशक, (अपील) और आयकर उपायुक्त (अपील) के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई है।

4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को 17 अगस्त, 1993 से एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। यह प्रावधान मुख्यतः चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई के चार महानगरों में न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के लिए है।

4.03 अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आई.सी.ए.डी.आर.) की स्थापना भारत में की गई है तथा इसे वैकल्पिक विवाद समाधान के विभिन्न

तरीकों द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान की तैयारी करने, उनका प्रचार करने, संवर्धन करने तथा लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

4.04 यह प्रावधान न्यायपालिका के लिए आधारदांचा संबंधी सुविधा देने हेतु बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता मुहैया कराने के लिए है।

4.05 यह व्यवस्था विधि अधिकारियों, विधि सलाहकारों और परामर्शदाताओं के लिए तथा निर्धनों को कानूनी सहायता मुहैया करवाने के लिए की गई है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के लिए प्रावधान भी शामिल है।

5.01 न्यायपालिका हेतु आधार दांचा संबंधी सुविधाओं की स्थापना से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की गई है। इस योजना में सरकारी तथा आवासीय दोनों प्रकार के भवनों, जिनमें उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय शामिल हैं, का निर्माण शामिल है। इस योजना के अंतर्गत व्यय को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा।

5.02 यह प्रावधान न्यायपालिका के लिए आधारदांचा संबंधी सुविधा देने हेतु विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान सहायता मुहैया कराने के लिए है।

5.03 अन्य कार्यक्रम - इसके अंतर्गत विधि आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ और विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा कानूनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है।

6. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए किया गया है।